www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

2 युवाओं व नारी सशक्तीकरण को समर्पित है...

3 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पीएमजी की...

4 क्या बॉन्ड गर्ल बनेंगी प्रियंका चोपड़ा?

वर्ष: 10 | अंक: 117 | दिल्ली, गुरुवार, 19 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

## संक्षिप्त समाचार

### हमें सत्ता से दूर रखने की साजिश-मायावती

**उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)।** उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने बुधवार को अपने समर्थकों को बीएसपी को सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रची जा रही तीव्र साजिशों और हथकंडों के प्रति आगाह किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने राज्य और देश भर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सभी अनुयायियों से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंबेडकरवादी आंदोलन को एकजुट करने और मजबूत करने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारे विरोधी हमें सत्ता से दूर रखने और हमारे खिलाफ साजिश रचने के और भी अधिक प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी अंबेडकरवादियों को आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। इससे पहले, उन्होंने पार्टी को कमजोर करने की साजिशों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इन साजिशों के प्रति सतर्क किया जाएगा।

### हम बार-बार झुकने वाले नहीं-एमके स्टालिन

**तमिलनाडु (एजेन्सी)।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में संविधान में संशोधन की मांग करते हुए राज्य सरकारों को स्वायत्त निकायों में बदलने की बात कही और केंद्र पर सारी शक्ति अपने पास रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया है जहां उसे अपने हक के फंड पाने के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें हर फंड के लिए केंद्र सरकार से लड़ना पड़ता है। कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे जहां वे देते हैं और हम लेते हैं? केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का पहला भाग विधानसभा में पेश कर दिया गया है।

### अमित शाह ने परमपूज्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के 152वीं जयंती समारोह को संबोधित किया

# श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता के गूढ़ संदेश को सरल तरीके से जन-जन तक पहुँचाकर आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया

**संजना भारती/पीआईबी**

**पश्चिम बंगाल।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नदिया में परमपूज्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के 152वें जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

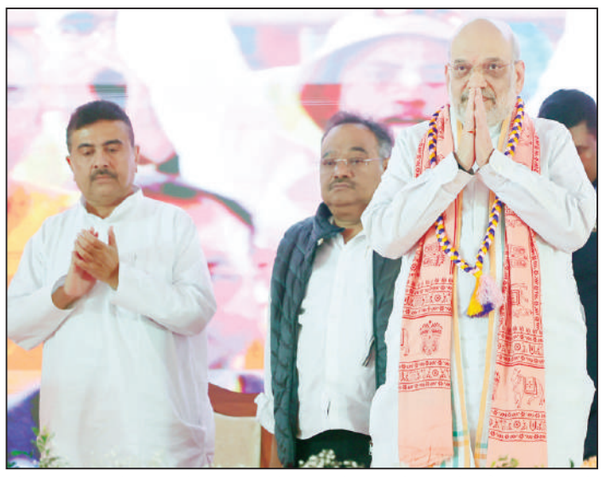

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मायापुर में भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किए गए भक्ति परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे आधुनिक बनाकर युवाओं और पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवनकाल में देश और दुनिया में अज्ञान के अंधकार से पीड़ित लाखों लोगों के उद्धार के लिए भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। श्री शाह ने कहा कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर श्रीकृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा हो जाता है और इसी रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, भक्तिसंगीत, नृत्य और गीता का गूढ़ संदेश बहुत सरल तरीके से जन-जन तक पहुँचाकर आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उन्होंने कहा कि उसी आंदोलन को परमपूजनीय भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसे आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं और पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज चैतन्य महाप्रभु के भक्ति-सेनापति और गौड़ीय मत के संस्थापक श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की 152वीं जयंती है। उन्होंने कहा कि एक अरब श्रीकृष्ण नाम जप का संकल्प पूर्ण कर श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने तप, त्याग और अनुशासन का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्रीकृष्णमय कर दिया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने धर्म को रूढ़ियों और संकीर्णताओं से मुक्त करते हुए यह सिद्ध किया कि आधुनिकता धर्म विरोधी नहीं, बल्कि उसकी साथी है। गृह मंत्री ने कहा कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रिंटिंग प्रेस को वृहद मृदंग का नाम देकर यह बताया कि प्रिंटिंग प्रेस में छपी पुस्तक सात समुंदर पार जाकर भी भक्ति का प्रचार करती है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति अचल और अनन्य हो तभी रुढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। जिनके मन में ईश्वर हैं वे अपने आप को सभी का दास कहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव के साथ शिष्य को छोटे से बड़ा करे। उन्होंने कहा कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सच्चे गुरु थे और उन्होंने ही गुरुपद का परिचय पूरे विश्व को कराया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी कई काम किए। श्री शाह ने कहा कि वैराग्य का मतलब सिर्फ संसार का त्याग कर देना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्रीकृष्ण की भक्ति में लगाना भी वैराग्य है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कई लोग भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जीवंत विश्वकोष भी कहते हैं। उन्हें गणित और संस्कृत का बहुत ज्ञान था लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कहा कि इस आध्यात्मिक केन्द्र से न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यह केन्द्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। मायापुर में इस्कॉन का विकसित हो रहा आध्यात्मिक केंद्र विश्व कल्याण का वैश्विक धाम बनेगा।

श्री शाह ने कहा कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जीवन में बहुत बड़े कामों में से एक था कि उन्होंने भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया।

# बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में नए CBWTF स्थापित होंगे: मंत्री सिरसा

**संजना भारती संवाददाता**

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्णायक नेतृत्व में दिल्ली सरकार पर्यावरणीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजधानी में नए कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में बायोमेडिकल कचरे की वर्तमान और भविष्य की अनुमानित स्थिति, संयंत्रों की तकनीकी विशेषताएं और कार्यान्वयन की रूपरेखा पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया।

प्रेजेंटेशन में बताया गया कि वर्तमान में दिल्ली के पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों से लगभग 40 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न हो रहा है।

भविष्य में बायोमेडिकल कचरे की अनुमानित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, नए प्रस्तावित कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की क्षमता 46 टन प्रतिदिन रखी गई है, जो लगभग 2300 किलोग्राम प्रति घंटा के बराबर होगी, तथा ये संयंत्र प्रतिदिन 20 घंटे तक संचालित किए जाएंगे। अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि पहले केवल दो संयंत्र पूरे दिल्ली के जिलों को कवर करते थे, जबकि नए प्रस्तावित संयंत्र अतिरिक्त भार को कम करेंगे जिससे बेहतर और समर्पित प्रबंधन संभव होगा। मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार अत्याधुनिक तकनीक से लैस और सभी वैधानिक पर्यावरण मानकों का पालन करने वाले नए पार्टनर्स को आमंत्रित करेगी। उन्होंने कहा, हम सर्वोच्च स्तर की तकनीक रखने वाली कंपनियों को अवसर देंगे, जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा।

पूर्व/उत्तर-पूर्व/शाहदरा और पश्चिम/दक्षिण-पश्चिम/मध्य क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित ये आधुनिक संयंत्र ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग और सुरक्षित लैंडफिल जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग-अलग किए गए कचरे का उपचार करेंगे, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरण पर प्रभाव कम होगा। जनस्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए श्री सिरसा ने कहा, बायोमेडिकल कचरे का सही निपटान दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अनियंत्रित कचरा गंभीर खतरा बन सकता है, जिसे हम सख्ती से रोक रहे हैं।

श्री सिरसा ने कहा, यह पहल प्रदूषण के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। कचरा प्रबंधन स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली बनाने का मूल आधार है। उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक निगरानी डैशबोर्ड भी स्थापित किए जाएंगे।

# नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार बनी सरकार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

### प्रदेश सरकार ने उचाना क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया: मुख्यमंत्री

**संजना भारती संवाददाता**

**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उचाना के विकास के पहिए को अब और भी तीव्र गति दी जाएगी और यहां की खुशहाली में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जींद के उचाना में बुधवार को धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए हैं। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं। इस दौरान प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा, विधायक श्री पवन खरखौदा भी मौजूद थे। रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। यह हरियाणा की वह धड़कन है, जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है, तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहां का युवा संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। उन्होंने कहा कि अन्न भण्डार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लम्बे समय से नजर अंदाज किया गया। झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो दो-दो-तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना हलके के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षों के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका और 15 का काम प्रगति पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1 हजार 409 करोड़ रुपये इस सरकार में खर्च किए गए हैं। जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 386 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में उचाना तहसील को उपमंडल और अलेवा उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया।

# राजेश कुमार पांडे ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला

**संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा**

**नई दिल्ली।** भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा के 1989 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने आधिकारिक तौर पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मूल निवासी श्री पांडे अपने नए पद पर एक समृद्ध शैक्षणिक अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एम.टेक किया। उन्होंने भारतीय रेलवे में अपने शानदार करियर की शुरूआत बरौनी में सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के रूप में की थी। तब से, उन्होंने रेलवे नेटवर्क में कई उच्च-स्तरीय भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें शामिल हैं:

**आरडीएसओ:** निरीक्षण निदेशक के रूप में, जहाँ उन्होंने गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल में सुधार किया।

**पूर्व मध्य रेलवे:** समस्तीपुर मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक और पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य किया।

**पश्चिम रेलवे:** विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया, विशेष रूप से मुंबई उपनगरीय खंड में 'एक्सल काउंटर' की स्थापना का नेतृत्व किया ताकि मानसून के दौरान सेवाएं प्रभावित न हों। श्री पांडे को प्रमुख बुनियादी ढांचा और सुरक्षा परियोजनाओं में उनके नेतृत्व के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।

डीआरएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, 'कवच' के विकास और कार्यान्वयन में भी एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं।

हाल ही में, रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (सिग्नल) के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने 400 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर 'कवच' की स्थापना की सफलतापूर्वक निगरानी की, जिससे रेल सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### उत्तर रेलवे के लिए विजन

उत्तर रेलवे की कमान संभालते ही श्री पांडे ने जोन के आधुनिकीकरण और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट खाका तैयार किया है:

1. **संरक्षा सर्वोपरि:** परिचालन में संरक्षा मानकों को मजबूत करना।
2. **गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण:** समयपालन (पंचुअलिटी) सुनिश्चित करना।
3. **बुनियादी ढांचा:** गुणवत्ता पर अटूट ध्यान देते हुए रेलवे बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास।
4. **संतुष्टि:** ग्राहक अनुभव और कर्मचारी कल्याण दोनों को बढ़ावा देना।
5. **नए महाप्रबंधक का मार्गदर्शक आदर्श वाक्य है:** 'राष्ट्र प्रथम, ग्राहक प्रथम, सर्वथा प्रथम'।

# समृद्ध, सुखद और सम्पन्न मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करेगा बजट 2026-27: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**एसबी संवाददाता**

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान आधारित विकास के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के ज्ञान के संकल्प में हमारी सरकार ने अब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के आई को भी शामिल किया है।

वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का यह बजट ज्ञानी के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर तैयार किया गया है। जिसमें गरीब कल्याण, युवा शक्ति के कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, अन्नदाता की आय में वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने का संकल्प है। वर्ष 2026-27 के 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए के बजट में विकास के लिए पर्याप्त धन राशि रखी गई है, यह विकास और जनकल्याण के संकल्प की पूर्ति का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट "समृद्ध मध्यप्रदेश, सम्पन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक मध्यप्रदेश" के सपने को साकार करने वाला है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कर बोझ नहीं डाला गया है। सुशासन और सुप्रबंधन के लिए निरंतर नवाचार और विकास के सभी पैमानों को पूरा करता यह बजट अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने के बाद यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा गया है। रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला संभवतः मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।

इस बजट से अगले तीन वर्ष के विकास का खाका खीचा जाएगा और यह बजट विकास के लिए सतत रूप से पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। यह बजट अमृतकाल 2047 के लिए विकास का पैमाना सिद्ध होगा। वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 18 लाख 48 हजार 274 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के अनुमान में 10.69 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए 28 हजार 158 करोड़ रूपए, आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 64 हजार 995 करोड़ रूपए, उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8 हजार 91 करोड़ रूपए, सुरक्षा चक्र के लिए 13 हजार 769 करोड़ रूपए सहित कृषि कल्याण के लिए कुल 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो किसान कल्याण वर्ष के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट व्यवस्था राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार अधोसंरचना विकास में बजट अनुमान 2026-27 का पूंजीगत परिव्यय रुपये 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। राज्य सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समुचित प्रावधान किए हैं। प्रदेश के गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

# किसानों को बनाया यूपी की समृद्धि का भागीदार

### योगी सरकार का गांव व किसान के समावेशी विकास पर लगातार फोकस

**संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा**

**लखनऊ।** भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव व अन्नदाता किसान सशक्त होंगे तो देश समृद्ध रहेगा और उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास का लक्ष्य भी तभी प्राप्त होगा। इसी नीति को केंद्र में रखते हुए योगी सरकार ने गांव और किसान को अपनी प्राथमिकता में रखकर बीते 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण किया है। यह नया उत्तर प्रदेश शहर व गांव के बीच अंतर को पाटता है, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकता है। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार का बजट 2026-27 भी खेती-किसानी और ग्राम्य विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाता दिखाई दे रहा है। यह ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देता है। किसानों को नई तकनीकों से, नए बाजारों से जोड़ता और उद्यमिता से जोड़ता है। खेती-किसानी व इससे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के नए माध्यमों को जन्म देता है। यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाता है।

2017 में सत्ता संभालने के तत्काल बाद योगी सरकार द्वारा किसानों की 36 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी से लेकर केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के 94,668.58 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने तक, डबल इंजन सरकार ने किसानों को आर्थिक समृद्धि के केंद्र में रखा है। डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ अकाउंट में देकर बिचौलियों का राज समाप्त किया गया। बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट कर देती है। यह राशि पिछले बजट के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करोड़ रुपये, एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करोड़ रुपये तथा किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर में परिवर्तित करने की योजना के लिए 673.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये बजट प्रावधान कृषि एवं सबद्ध क्षेत्रों के तकनीकी उन्नयन में मददगार होंगे।

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बार फिर मजबूती दी गई है। प्रदेश के सभी जनपदों को शामिल करते हुए 94,300 हेक्टेयर में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना संचालित है। बजट में इसके लिए 298 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निजी नलकूपों को अनवरत बिजली आपूर्ति हो, इसका ध्यान रखा गया है। इसके लिए 2400 करोड़ प्रस्तावित हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम पर लगातार कार्यरत है।

# सम्पादकीय

## संगठन से समाज तक की यात्रा

**जानाधारित** संगठन की कल्पना बहुत पुरानी है। 'एकता परिषद' को हमने हमेशा एक जन-संगठन के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रक्रिया में लंबे समय तक जनता की भागीदारी सशक्त रही है, भले ही कार्यकर्ताओं का सहयोग बाहर से मिलता रहा हो। इसलिए अब तक इसे पूर्ण रूप से जन-संगठन मानना कठिन हो रहा था, जबकि कार्यकर्ता उसी समाज से आए हुए थे, जिस समाज के हित में संघर्ष हो रहा था। इन सीमाओं के बावजूद 'एकता परिषद' एक जन-संगठन के रूप में लम्बे समय से काम करता रहा। 'जनादेश 2007,' 'जनसत्याग्रह 2012' और 'जनांदोलन 2018' के आन्दोलनों ने संगठन को मजबूत बनाया और इसी मजबूती के आधार पर सरकार की नीतियों को बदलने में हम लोग सफल हुए। 'वनाधिकार अधिनियम,' '10 सूत्रीय आगरा समझौता और 'भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति 2013' आदि इस बात का उदाहरण हैं कि एक व्यवस्थित जन-संगठन के सहारे काफी हद तक नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है। इन तमाम नीतियों और कानूनों के सहारे जमीनी स्तर पर जो बदलाव आया है उसे देखने और समझने के लिए मैंने पिछले दिनों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा किया। वनाधिकार के तहत भूमि प्राप्त 25,000 किसानों के साथ दमोह और कटनी में महत्वपूर्ण काम हो रहा है। उन किसानों के साथ काम करने वाले करीब 60 कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने का प्रत्यक्ष मौका मिला। इन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला उससे मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं। ऐसा लगता है कि 25,000 परिवार नैसर्गिक खेती के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। वे स्वयं जल, जंगल, जमीन को व्यवस्थित कर रहे हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक हालातों को सुधार रहे हैं। अब ये परिवार किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे उलटा संगठन को मदद करने की स्थिति में हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन भूमिहीनों को संगठित करने के लिए 10 कार्यकर्ता लम्बे समय तक काम करते रहे थे, वहां अब 25,000 किसान कार्यकर्ता हैं जो स्वयं अपनी दम पर अन्य भूमिहीन लोगों के लिए काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संगठन की व्यापकता के लिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इससे एक बात साफ हो रही है कि एक समय जो संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित था, अब वह पूर्ण रूप से जनाधारित संगठन बन चुका है। अब जन-संगठन की कल्पना साकार होते हुए दिखाई पड़ रही है। इस यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश के उमरिया जिले से आए आदिवासी किसानों से भी चर्चा करने का मौका मिला। इनके अनुमान के अनुसार उमरिया एवं शहडोल जिले के करीब 25,000 आदिवासियों को 'वनाधिकार' के तहत जमीन मिल चुकी है। लगभग 2 एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से भी गणना करें, तो करीब 50,000 एकड़ जमीन भूमिहीनों को मिल चुकी है। कल जो अपने आपको भूमिहीन मान रहे थे, वे अपने आप को आज किसान कहने लगे हैं। इस संवाद में मीरा बहन भी शामिल थीं जो स्वयं एक गोंड़ आदिवासी परिवार से हैं। मीरा बहन ने अपने खेत को इस ढंग से सजाया है कि रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति खड़े होकर उनके खेत को निहारता है। मीरा बहन के अनुसार, जिन आदिवासियों को जमीन प्राप्त हुई है उनमें से करीब 80 प्रतिशत लोग अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं और स्वावलम्बन की ओर बढ़ रहे हैं। मीरा बहन की बात को उनके सहयोगी महिपाल बैगा, धर्मदास सिंह, मास्टर साहब ने भी सही करार दिया। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 20 प्रतिशत लोग जिन्हें खेती करने में कठिनाई हो रही है, उन्हें संगठन के द्वारा मदद पहुंचानी होगी, ताकि वे भी अन्य लोगों की तरह स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ सकें। उनका अनुमान है कि 'वनाधिकार कानून' के तहत आवेदन दे चुके आदिवासियों में 50 प्रतिशत लोगों को अभी भूमि अधिकार मिलना बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन परिवारों को भी 'वनाधिकार' के तहत जमीन जल्दी प्राप्त होगी। इन मित्रों के अनुमान के अनुसार अब उमरिया, शहडोल जिलों में 25,000 परिवार ऐसे हैं जो जन-संगठन को अपनी ही दम पर आगे ले जा सकते हैं। उनके अनुसार जो परिवार भूमि-स्वामी बने हैं, वे निःसंकोच हर साल एक क्विंटल अनाज संगठन की व्यापकता के लिए देना चाहेंगे। एक कार्यकर्ता आधारित संगठन अब तेजी से जन-संगठन बनता जा रहा है। चर्चा के दौरान इन मित्रों के चेहरे पर जो उत्साह देखने को मिला, उससे मुझे भरोसा होने लगा है कि जन-संगठन की कल्पना अब तेजी से साकार होती जा रही है। अगर कटनी, दमोह, उमरिया, शहडोल में हजारों किसान अपनी ही दम पर संगठन को आगे ले जाने की तैयारी में हैं तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि यही तस्वीर अन्य जिलों में भी देखने को मिलेगी। टीकमगढ़ जिले का संगठन बहुत दिनों से बिना किसी सहयोग के संगठनात्मक गतिविधियों को अपनी दम पर आगे बढ़ा रहा है। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, सिवनी, सीधी और सतना से भी ऐसी ही खबरें निरन्तर मेरे पास आ रही हैं। 40 साल के लम्बे अंतराल की संगठन की यात्रा संस्थाओं से प्रारम्भ होकर कार्यकर्ताओं की ओर और अब कार्यकर्ताओं से आम ग्रामीणों की ओर चल पड़ी है। अब जरूरत इस बात की है कि अनुभवी कार्यकर्ता जो लम्बे समय से एक जन-संगठन का सपना देख रहे थे वे इस प्रक्रिया को गतिशील बनाने और जन-संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुट जावें। अब इस जन-संगठन के माध्यम से शेष भूमिहीनों को भूमि दिलाने का काम संगठन को अपने हाथ में लेना होगा। संगठन की संरचना के पीछे गांधी और विनोबा का जो आदर्श प्रबल योग रहा है उन आदर्शों को साकार करना आज की आवश्यकता है। हम सबके प्रयासों से संगठन ने जो लम्बा रास्ता तय किया है, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। यह नमूना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनकर प्रेरणा दे सकता है।

**संजना भारती दैनिक**

**भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।**

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-संजय कुमार द्वारा आर.डी. प्रिंट एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। मुद्रक-देवानंद राय।
RNI No. : DELHI/2016/70240
Phone No. : 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

# युवाओं व नारी सशक्तीकरण को समर्पित है यूपी बजट

**युवाओ के लिए पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार सृजन करने की व्यवस्था बजट में की गई है ।इसके लिए युवा पर्यटन क्लब बनाए जाएंगे। युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। गोरखपुर में स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट अलीगढ़ को उच्चीकृत कर स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनाया जाएगा**

-मृत्युंजय दीक्षित

**विगत** कुछ माह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसमुदाय को सरकार के निर्णयों से अवगत कराने के लिए पाती लिखने का अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इस बार बजट के बाद लिखी अपनी पाती में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की विशेषताओ पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह बजट युवाओं व नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश का यह बजट नवाचार का बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों की यह यात्रा प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

मुख्यमत्री योगी पूर्व में भी कह चुके हैं कि विगत नौ वर्षों में यूपी असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश बन चुका है। इस बजट में युवाओं को रोजगार उपलबध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को विकसित करते हुए वृहद निवेश की नई योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। उभरती हुई नयी तकनीकीकी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। प्रदेश में पहली बार स्टेट डेटा अथारिटी का गठन करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। यह प्रदेश में वास्तविक समय पर आंकड़ों के संग्रह और इसके अनुश्रवण के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश एआई मिशन, एआई डेटा लैब, एआई सेंटरऑफ एक्सीलेंस तथा डेटा सेंटर क्लस्टर प्रदेश को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एआइ एवं डीप टेक के क्षेत्र में एक एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे। बजट के अनुसार टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। बजट में एआई को प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत प्रदेश की 49 आईटीआई में एआइ लैब स्थापित की जाएगी। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई ठेटा लैब की स्थापना के लिए 32.32 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साइबर सुरक्षा को भी बजट में अहम स्थान मिला हे। प्रदेश में पहली बार स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर हब बनने जा रहा है इस कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यू -हब का मुख्यालय लखनऊ और दूसरा इन्क्यूबेटर गौतमबुद्धनगर में बनाया जाएगा। यू-हब से ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ।राजधानी के परिषदीय विद्यालयों को एआई से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को परंपरागत के साथ आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा मिलेगी।

युवाओ के लिए रोजगार के नए क्षेत्रो का सृजन किया जा रहा है। हथकरघा, पावरलूम और गारमेंटिंग सेक्टर में रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 30 हजार रोजागर सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 -27 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उत्पादन के लिए 10 करोड़ और खजनी गोरखपुर स्थित कम्बल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

युवाओ के लिए पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार सृजन करने की व्यवस्था बजट में की गई है ।इसके लिए युवा पर्यटन क्लब बनाए जाएंगे। युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। गोरखपुर में स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट अलीगढ़ को उच्चीकृत कर स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनाया जाएगा। वहीं युवा पर्यटन क्लबॉन के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। बजट मे एमएसएमई सेक्टर को पर्याप्त धन मिलने से लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को बढ़ावा मिलने से युवाओ के लिए रोजगार और नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। युवाओ के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में खेल विद्यालय व मैदान बनाने की योजना है जिसके अंतर्गत 2030 के कामनवेल्थ गेम्स एवं 2036 के ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं को निखारा जाएगा।

महिला एवं बाल विकास के लिए कुल 18,620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना एवं जनपद स्तर पर श्रमजीवी महिला छात्रावास प्रस्तावित है। बजट मे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि महिला क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 151.04 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में दुग्ध कंपनियों का गठन कर दुग्ध संग्रहण व विपणन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 3500 करोड़ रुपए, छात्रावासो के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए 35 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अतंर्गत भवन निर्माण के लिए 80 करेड रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में इस बार धन का आवंटन इस प्रकार से किया गया है यदि सरकार आगे कोई बड़ी योजना घोषित करती है तो उसके लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध रहे जैसे किअभी बुजुर्ग और वृद्ध महिलाओ के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि करने से लेकर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निःशुक्ल यात्रा की व्यवस्था प्रस्तावित है।नवरात्रि के अवसर पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं जिनके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार के बजट को लेकर महिलाओं का कहना है कि इस बर के बजट से बेटियों की पढ़ाईसे लेकर विअव्ह तक की चिंता कम होरही है। यह बजट गरीब महिलाओं को व्यापक रूप से सहारा देने वाला है। इस बजट से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढेगी। स्वयं सहायता समूहो के लिए की गई घोषणाओं से महिला समूह के उत्पादों को बाजार दिलाने से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

# भारत के लिए बड़ा सबक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद

**दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्विद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है**

-संतोष कुमार पाठक

**राजधानी** दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 के लगभग वैश्विक एआई अग्रणी भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी तरह के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहा भारत, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर दावा भी किया है कि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी, प्रख्यात शोधकर्ता, बहुपक्षीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक एक साथ आएंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे।

राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्विद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जाहिर सी बात है कि इस समिट के जरिए जहां चर्चा भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता और टैलेंट की होनी चाहिए थी, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली एआई समिट में पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एक प्रोफेसर ने बड़े ही गर्व के साथ चार पैरों वाले इस रोबोडॉग की खासियत भी कैमरे पर बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस प्रतिनिधि के हाव-भाव देखने लायक है।इसका नाम 'ओरियन' बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है। सरकारी चैनल सहित देश के कई मीडिया संस्थानों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोर-शोर से चलाया और छापा भी। लेकिन चीन की तरफ से बयान आते ही पूरा मामला पलट गया। इसके बाद यह पता लगा कि वास्तव में यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया गया एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है।

विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि यह रोबोडॉग उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए यह भी कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे बनाने का दावा नहीं किया। जबकि उनके प्रोफेसर का वायरल वीडियो ही उनके झूठ का पदार्फाश कर रहा है।

ऐसे में एक बार फिर से सरकार के विजन, नीति और फंड की व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार प्राइवेट विश्विद्यालय और कॉलेजों के सहारे देश में नई, बड़ी और स्पेशल रिसर्च नहीं करवा सकती क्योंकि इनकी भूमिका और इनके कामकाज का पूरा ढांचा ही संदिग्ध है। एडमिशन से लेकर क्लास और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी कई बार गहरे सवाल खड़े हो चुके हैं। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट फाइल करने के नाम पर निजी विभविद्यालयों को जो मोटा फंड देती है, उसकी न्यायिक जांच करवाने का भी समय आ गया है।

दरअसल, यह बिल्कुल सही समय आ गया है कि सरकार पहले की तरह सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्विद्यालयों में शिक्षा हासिल कर रही प्रतिभाओं को हर तरह से उभारने में मदद करें। इन संस्थानों में फीस और लालफीताशाही दोनों कम होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और करप्शन पर हर हाल में लगाम होनी चाहिए।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

**खेल/विदेश/कारोबार**

## 40 फीसदी कम...कितने फीसदी कम हो गया रूस से भारत का आयात?

(एजेन्सी)।

**जनवरी** 2026 में रूस से भारत का सामान इम्पोर्ट तेजी से गिरा है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के नए ट्रेड डेटा से पता चलता है कि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इम्पोर्ट लगभग 40 परसेंट गिरा है, जो $4.81 बिलियन से घटकर $2.86 बिलियन हो गया है। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण भारतीय रिफाइनर कंपनियों द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारी कमी है। रूस से भारत का ज्यादातर इम्पोर्ट कच्चा तेल होता है, जो आमतौर पर कुल इम्पोर्ट का लगभग 80 परसेंट होता है। अनुमान है कि जनवरी में रूस से भेजे गए तेल शिपमेंट की कीमत लगभग $2.3 बिलियन या उससे भी कम थी। भारत रूस से कोयला, फर्टिलाइजर, लोहे के सामान, अखबारी कागज, दालें और कीमती पत्थर भी खरीदता है।

रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में गिरावट रातों-रात नहीं हुई। यह तब शुरू हुई जब पिछले साल अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी और ट्रेड प्रेशर लगाया, जिससे रूस से तेल इंपोर्ट कम करने पर दबाव पड़ा। इन उपायों में भारतीय सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाना शामिल था, जो 2025 के बीच में रूस से तेल खरीदने से जुड़ी पेनल्टी के तौर पर तेजी से बढ़ गया। इस वजह से, भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में कटौती शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे जनवरी में रूस से क्रूड ऑयल की कोई डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। दूसरी रिफाइनर कंपनियों ने भी ज्यादा लागत और ट्रेड पेनल्टी से बचने के लिए अपनी खरीद कम कर दी।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में रूस से इंपोर्ट कम होता रह सकता है। भारतीय रिफाइनर अब वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट के देशों सहित दूसरे सोर्स से सस्ते तेल पर नजर गड़ाए हुए हैं।

यह बदलाव रूसी क्रूड पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो कुछ हद तक इंटरनेशनल ट्रेड बातचीत और आर्थिक दबावों से प्रेरित है। हाल ही में यूएस सरकार ने प्यूनिटिव टैरिफ कम किए हैं। यह बदलाव भारत की ट्रेड पोजीशन में मदद कर सकता है और साथ ही इसकी एनर्जी सप्लाई चेन को भी नया आकार दे सकता है।

## शिवम दुबे का तूफानी अर्धशतक

(एजेन्सी)।

**भारत** ने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में एक भी मैच न हारने के बाद टी20 विश्व कप 2026 के सुपर आठ में अपराजित रहते हुए प्रवेश किया है। इतिहास रचने की उम्मीद में, मौजूदा चैंपियन भारत ने बुधवार, 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराया। भारत ने लीग चरण में अपने सभी चार मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अहमदाबाद में थोड़ी धीमी पिच पर बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने नीदरलैंड्स की जुझारू चुनौती को रोकने में कामयाबी हासिल की।

इस से पहले शिवम दुबे के तूफानी अर्धशतक से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बुधवार को यहां नीदरलैंड के खिलाफ धीमी शुरूआत से उबरते हुए छह विकेट पर 193 रन बनाए। दुबे ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 31 गेंद में छह छक्कों और चार चौकों से 66 रन की पारी खेलने के अलावा हार्दिक पंड्या (21 गेंद में 30 रन, तीन छक्के) के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 गेंद में 76 रन की साझेदारी की जिससे भारत अंतिम पांच ओवर में 75 रन जोड़ने में सफल रहा। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (34) और तिलक वर्मा (31) ने भी उपयोगी पारियां खेली। नीदरलैंड की ओर से तेज गेंदबाज लोगान वान बीक सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 56 रन देकर तीन विकेट चटकाए। ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त ने 19 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अभिषेक शर्मा का मौजूदा विश्व कप में खाता खुलने का इंतजार जारी रहा और वह लगातार तीसरे मैच में बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। वह आर्यन की सीधी गेंद को पूरी तरह से चूककर बोल्ड हुए। तिलक ने वान बीक पर छक्का मारा जबकि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे इशान किशन (18) ने भी इस तेज गेंदबाज पर चौका जड़ा। इशान ने कोलिन एकरमैन का स्वागत छक्के के साथ किया जबकि अगले ओवर में दत्त पर भी चौका जड़ा लेकिन इस ऑफ स्पिनर की अगली गेंद उनकी जांघ और फिर कोहनी से टकराकर विकेटों में समा गई। भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 50 रन बनाए। सूर्यकुमार 13 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब वान बीक की गेंद पर माइकल लेविट ने उनका कैच टपका दिया।

## परमाणु वार्ता फेल! अचानक ईरान ने दागी मिसाइलें!

(एजेन्सी)।

**जिनेवा** परमाणु वार्ता फेल टकराव की ओर दुनिया ईरान अमेरिका आमने-सामने बड़े युद्ध की आहट दुनिया एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सैन्य तनाव के साए में जिनेवा में हुई अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। 3 घंटे चली इस अहम बैठक से उम्मीद थी कि परमाणु मुद्दे पर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद तस्वीर और ज्यादा धुंधली नजर आ रही है। इसी बीच ईरान ने होरमूर स्टेट में मिसाइल अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है।

ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में हुई परोक्ष वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक यह बैठक करीब 3 घंटे चली लेकिन किसी ठोस सहमति पर नहीं पहुंच सकी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव की आग में झुलस रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। जबकि ईरान ने इसे सीधे-सीधे उकसावे की कारवाई बताया है। इसी तनाव के बीच ईरान ने होरमुट स्टेट में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि सभी मिसाइलों ने अपने तय लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। ईरान ने हॉर्मोस जल डमरू मध्य की दिशा में मिसाइलें दागने का अभ्यास शुरू कर दिया। सरकारी एजेंसी के मुताबिक रेवोलशनरी गार्ड से जुड़ी मिसाइलें ईरानी जमीन तट और दुप्पल से दागी गई है। सभी ने अपने टारगेट को सटीक तौर पर निशाना बनाया। अभ्यास से क्षेत्रीय सुरक्षा पर तनाव बढ़ने की आशंका भी है।

## हरित ऊर्जा की ओर भारत के बढ़ते कदम!

(एजेन्सी)।

**भारत** ने ऊर्जा स्वतंत्रता और स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत की गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता अब 272 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह घोषणा 'भारत-ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल' की शुरूआत के दौरान की गई, जिसमें ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी मौजूद थीं। कार्यबल की औपचारिक शुरूआत के मौके पर जोशी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 35 गीगावाट से अधिक सौर तथा 4.61 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्त्रोतों से हासिल किया। यह उपलब्धिक निर्धारित लक्ष्य से पांच वर्ष पहले हासिल की गई। मंत्री ने कहा, आज भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता 272 गीगावाट से अधिक है जिसमें सौर से 141 गीगावाट और पवन से 55 गीगावाट है...। हमारी व्यापकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो साल से कम समय में करीब 30 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर की सुविधा मिली।

इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत 21 लाख पंपों का सौरकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय तथा निवेशकों और उद्योग के भरोसे को दशार्ते हैं। मंत्री ने कहा कि हालांकि अगले चरण में विश्वसनीयता, ग्रिड स्थिरता, औद्योगिक गहराई तथा ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। जोशी ने कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा की, अगली अवस्था में रणनीतिक भूमिका होगी और इसके लिए गुजरात तथा तमिलनाडु के तटों के पास कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि शुरूआती 10 गीगावाट अपतटीय निकासी क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु में पांच-पांच गीगावाट) के लिए पारेषण योजना पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए 7,453 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि योजना भी शुरू की गई है जो लगभग 71 करोड़ पाउंड के बराबर है। मंत्री ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपतटीय पवन वैश्विक ऊर्जा बदलाव के सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक है। इसके लिए विशेष बंदरगाह ढांचा, समुद्री लॉजिस्टिक, समुद्र तल पट्टे की मजबूत व्यवस्था, व्यवहार्य व्यावसायिक ढांचे आदि की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से यह कार्यबल महत्वपूर्ण है। भारत-ब्रिटेन दृष्टिपत्र 2035 और चौथे ऊर्जा संवाद के तहत इस कार्यबल का गठन भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा परिवेश को रणनीतिक दिशा एवं समन्वय देने के लिए किया गया है। जोशी ने कहा कि ब्रिटेन ने शुरूआती तैनाती से लेकर परिपक्व आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले बड़े व्यावसायिक बाजारों तक अपतटीय पवन के विस्तार में वैश्विक नेतृत्व दिखाया है। उन्होंने कहा, भारत व्यापकता, दीर्घकालिक मांग और तेजी से बढ़ता स्वच्छ ऊर्जा तंत्र लेकर आता है। हम मिलकर तीन व्यावहारिक स्तंभों पर काम कर सकते हैं। पहला स्तंभ पारिस्थितिकी योजना एवं बाजार संरचना है जिसमें समुद्र तल ढांचे को बेहतर बनाना, ग्रिड तैयारी के अनुरूप निविदा समयरेखा तय करना और पारदर्शी राजस्व सुनिश्चितता तंत्र बनाना शामिल है। मंत्री ने कहा कि दूसरा स्तंभ ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला है। इसमें बंदरगाह आधुनिकीकरण, आधार संरचनाओं, टावरों, पंखों और केबलों का स्थानीय निर्माण, विशेष पोत तथा समुद्री परिचालन के लिए कौशल विकास शामिल है।

वहीं तीसरा स्तंभ वित्तपोषण एवं जोखिम न्यूनीकरण है जिसमें मिश्रित वित्त ढांचे, शुरूआती जोखिम घटाने वाले उपकरण तथा दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी का उपयोग करना शामिल है। उन्होंने कहा कि अपतटीय पवन की पारेषण योजना, भंडारण समाधान और उभरते तटीय हरित हाइड्रोजन समूहों से भी जोड़ना होगा। जोशी ने कहा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन की कीमत घटकर सबसे कम 279 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यबल वास्तव में विश्वास बल है जो दर्शाता है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर जमीनी स्तर पर पेश होने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।

## पाकिस्तान की सुपर-8 में एंट्री, नामीबिया को 102 रनों से रौंदा

(एजेन्सी)।

**बता** दें कि टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस पारी के नायक रहे साहिबजादा फरहान, जिन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और चार छक्के शामिल रहे। गौरतलब है कि टी20 विश्व कप इतिहास में यह उनका पहला शतक रहा, जिसने टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई।

फरहान को सलमान अली आगा का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 23 गेंदों पर 38 रन जोड़े। शादाब खान ने भी 22 गेंदों में 36 रन बनाकर अंतिम ओवरों में तेजी दी। आखिरी पांच ओवरों में रन गति बढ़ने से पाकिस्तान 200 के करीब पहुंच सका, जो इस पिच पर प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जा रहा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरूआत संभली हुई रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। लौरें स्टीनकैंप ने 23 और अलेक्जेंडर वोल्सेंक ने 20 रन बनाए, मगर बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके। पूरी टीम 17.3 ओवर में 97 रन पर सिमट गई।

गेंदबाजी में उस्मान तारिक ने चार विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। शादाब खान और अन्य गेंदबाजों ने भी कसी हुई लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मौजूद जानकारी के अनुसार, यह जीत पाकिस्तान के नेट रन रेट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ग्रुप ए में अमेरिका के साथ अंक तालिका की जंग काफी करीबी थी।

# मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पीएमजी की बैठक में पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की हुई समीक्षा

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय**

**हाजीपुर।** मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैशाली जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कल्याणपुर (हाजीपुर) से वेला नवादा (दरभंगा) तक फोरलेन एनएच-119D राजमार्ग निर्माण, भारतमाला एलओटी-07 अदलवारी-मणिकपुर खंड (एनएच-139डब्लू) राजमार्ग निर्माण, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बैठक के उपरांत जिलाधिकारी, वर्षा सिंह ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अर्जन, मुआवजा भुगतान एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करते हुए सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

# परीक्षाएं ज्ञान की आजमाईश के लिए हैं, निडरता और ईमानदारी से परीक्षा दें: हरजोत सिंह बैंस

**संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा**

**चंडीगढ़।** पंजाब भर में 8.18 लाख से अधिक विद्यार्थी 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने निष्पक्षता, अनुशासन और नकल के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा और निगरानी के लिए व्यापक ढांचागत व्यवस्था की है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर लीक के जोखिमों को समाप्त करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, तकनीकी आधारित प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत 384 उड़न दस्तों सहित विशेष टीमें तैनात की गई हैं जो अचानक निरीक्षण करेंगी, प्रश्न पत्रों की रीयल टाइम ट्रैकिंग के लिए एम.ए.टी.क्यू.ऐप पेश की गई है और परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। 6,792 परीक्षा केंद्र स्थापित करके और 5,600 से अधिक अधिकारियों को तैनात करके पंजाब की शिक्षा प्रणाली निर्विघ्न, भरोसेमंद और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, जो शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए, श्री हरजोत सिंह बैंस ने उन्हें आत्मविश्वास और ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

# महुआ में विशेष छापेमारी में दो बाल श्रमिक मुक्त, नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय**

**हाजीपुर।** जिलाधिकारी, वैशाली, वर्षा सिंह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा 18 फरवरी 2026 को महुआ प्रखंड क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस सघन कार्रवाई में महुआ क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से 02 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों बालकों से प्रतिबंधित श्रेणी का कार्य कराया जा रहा था जो कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तत्पश्चात दोनों बच्चों को तत्काल मुक्त कराते हुए बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित नियोजक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

श्रम अधीक्षक, वैशाली ने बताया कि बाल श्रम कराने वाले नियोजक पर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा कारावास का प्रावधान है। मुक्त कराए गए प्रत्येक बाल श्रमिक के बैंक खाते में नियोजक से 20,000 रुपये की वसूली कर जमा कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योग्य बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता स्वरूप 3,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी।

जिलाधिकारी, वर्षा सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में बाल श्रम के विरुद्ध निरंतर सघन अभियान चलाया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा से जुड़ाव एवं अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस छापेमारी अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रही।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बाल श्रम से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी प्रशासन को दें ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

# नगरपालिका राजौंद में 20 फरवरी को होगी एरिया सभा बैठक

## हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदको के कागजात सत्यापन व वार्ड समस्याओं पर होगा विचार-विमर्श: नपा सचिव

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार**

नपा सचिव नरेंद्र शर्मा।

**राजौंद।** नपा सचिव राजौंद नरेंद्र शर्मा द्वारा बुधवार को नपा परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होनें बताया कि 20 फरवरी, शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नगरपालिका राजौंद परिसर में नगर के सभी 13 वार्डों की संयुक्त एरिया सभा बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक के दौरान हरियाणा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन तथा लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के कागजातों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही एरिया सभा सदस्यों एवं वार्ड प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने वार्डों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। नपा सचिव ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन ने सभी वार्ड पार्षदों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया है। साथ ही नगर क्षेत्र के नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में बैठक में भाग लें और हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर, योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने सुझाव प्रस्तुत कर प्रशासन के साथ सहयोग करें।

# सोंगरी के राजकीय आरोही मॉडल स्कूल में प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न

## छठी, नवीं व 11वीं कक्षा के लिए 312 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, परिणाम 28 फरवरी को

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार**

राजकीय आरोही मॉडल स्कूल सोंगरी में प्रवेश परीक्षा में भाग लेते विद्यार्थी। (छाया: एसबी)

**राजौंद।** जिला कैथल के गांव सोंगरी स्थित राजकीय आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोंगरी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 18 फरवरी, बुधवार को प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। यह परीक्षा छठी, नवमी और 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा में छठी कक्षा के 174, नवमी कक्षा के 85 तथा 11वीं कक्षा के 53 विद्यार्थियों सहित कुल 312 छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा निर्धारित समयानुसार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और विद्यार्थियों ने अनुशासन का पूर्ण पालन किया।

विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सुनीता आहुजा ने बताया कि प्रवेश परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों का चयन कर विद्यालय में रिक्त सीटों को मेरिट के आधार पर भरना है, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता को और सुदृढ़ किया जा सके। परीक्षा को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा अलग-अलग कक्षों में बैठने की समुचित व्यवस्था की गई, पहचान पत्रों की जांच की गई तथा पर्यवेक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की गई। विद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश परीक्षा का परिणाम 28 फरवरी को घोषित किया जाएगा।

# स्वच्छ सर्वेक्षण के मद्देनजर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा हुई सख्त

**एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी**

**करनाल।** आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के मद्देनजर शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केट कमेटी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, वन विभाग तथा हरियाणा रोडवेज करनाल के प्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा व जोन इंचार्ज मौजूद रहे।

बैठक में निगमायुक्त ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने के कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने एक सप्ताह का समय देते निर्देश दिए कि कहीं भी कूड़े-कचरे के ढेर या गदंगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। सफाई व्यवस्था को समय रहते दुरूस्त कर लिया जाए। एक सप्ताह बाद औचक निरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सफाई निरीक्षक व सभी जोन इंचार्ज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया था, जिसमें कुछ जगहों पर गंदगी व कूड़ा-कर्कट बिखरा हुआ पाया गया। उन जगहों की सूची सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सौंपते हुए निगमायुक्त ने जल्द से जल्द कार्रवाई कर दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया गया तो अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सम्बंधित विभाग के मुख्यालय को लिखा जाएगा। उन्होंने स्पष्टद किया कि शहर की सफाई व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने मार्केट कमेटी प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि मंडी परिसर की नियमित साफ-सफाई करवाई जाए। जरूरत अनुसार ट्विन बिन लगवाए जाएं तथा आवारा पशुओं को आने न दिया जाए। सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे का पृथक्करण किया जाए। मंडी में मौजूद सभी दुकानदारों व वैंडर्स को इसके लिए सख्ती से बोला जाए।

एन.एच.ए.आई. प्रतिनिधि को हाईवे की विशेष सफाई तथा नाला की टूटी हुई स्लैब को बदलने के निर्देश दिए। वन विभाग, हरियाणा रोडवेज करनाल तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम केप्रतिनिधियों को अधिनस्थ क्षेत्र की सफाई करवाने को कहा गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को सम्बंधित सेक्टर, पार्क, ग्रीन बेल्ट व खाली प्लॉट की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

# करनाल धान घोटाला: जांच की दिशा पर उठे सवाल, बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

**एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी**

**करनाल।** भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने करनाल में सामने आए करोड़ों रुपये के धान घोटाले की जांच पर गंभीर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल सरकारी लापरवाही या कागजी त्रुटि का नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित अपराध प्रतीत होता है, जिसमें प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता।

रतनमान ने जारी बयान में कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी न होना जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक असली सरगना और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त षड्यंत्रकारी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, तब तक जांच को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है, ताकि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके। यदि बड़े दोषियों को बचाया गया तो यह साफ संकेत होगा कि जांच दबाव में की जा रही है, रतनमान ने कहा। उन्होंने मांग की कि घोटाले में शामिल सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पदार्फाश किया जाए।

रतनमान ने जानकारी दी कि 24 फरवरी को कुरुक्षेत्र स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की राष्ट्रीय बैठक में करनाल धान घोटाले का मुद्दा विशेष एजेंडे में शामिल किया जाएगा। बैठक में देशभर के किसान नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी और सरकार पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस दबाव बनाया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बड़े राजनीतिक चेहरों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भाकियू किसानों के हक में आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और किसानों का पैसा सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

# सब सेंटर किठाना में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ शपथ व जागरूकता अभियान आयोजित

## स्वास्थ्य कर्मियों व ग्रामीणों ने बालिका शिक्षा व सुरक्षा को लेकर लिया संकल्प

सब सेंटर किठाना में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। (छाया: एसबी)

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार**

**राजौंद।** जिला कैथल सीएमओ डॉ रेनू चावला के निर्देश व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजौंद डॉ. संदीप सिंह के मार्गदर्शन तथा एच आई कुलदीप सिंह के सहयोग से सब सेंटर किठाना में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शपथ एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना तथा शिक्षा के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

इस अवसर पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने बालिका भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि बेटियां समाज की रीढ़ हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई और जागरूकता बैनर के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में सभी आशा वर्कर, प्रदीप शर्मा एमपीएचडब्ल्यू (एम), डॉ. अनिल कणाव तथा गीता रानी एएनएम उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान आशा वर्करों को घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा बालिकाओं की पढ़ाई के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। अंत में सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

# निजी बस में सरकारी स्कूल के छात्रों से अभद्रता, छत पर बैठकर सफर कराने का आरोप

## अभिभावक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की सख्त कार्रवाई की मांग

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार**

**राजौंद।** राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ निजी बस में हुए कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता व अभिभावक निर्मल कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को भेजी शिकायत में बताया कि उनका बेटा राजौंद के सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी हैं। वह 17 फरवरी, मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद शाम करीब 3 बजे निजी बस 'दी जगदम्बा' बस संख्या HR45B7725 से लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव नीमवाला जा रहा था।

आरोप है कि बस के परिचालक ने सरकारी स्कूल के गांव नीमवाला के विद्यार्थियों को धमकाते हुए कहा कि इस बस में सरकारी स्कूल के बच्चे निःशुल्क यात्रा नहीं कर सकते। परिचालक ने छात्रों से टिकट लेने या बस से नीचे उतरने को कहा। इतना ही नहीं, कथित रूप से यह भी कहा गया कि यदि फ्री में सफर करना है तो बस की छत पर बैठकर यात्रा करें। बताया गया कि जिन छात्रों के पास टिकट के पैसे नहीं थे, उन्हें मजबूरी में बस की छत पर बैठकर सफर करने के लिए बाध्य किया गया।

अभिभावक ने इसे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि इस तरह की यात्रा किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती थी।

इस संबंध में अभिभावक निर्मल कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को शिकायत भेजकर बस 'दी जगदम्बा', बस संख्या HR45B7725 के परिचालक व मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

# सरकार सिरसा से पलवल तक साफ पीने का पानी देने में नाकाम: सैलजा

## गंदे पानी ने तबाही मचा दी है, कहीं हेपेटाइटिस तो कहीं कैंसर का हो रहा है प्रकोप

**एसबी विशेष संवाददाता**

**चंडीगढ़।** पलवल जिले के छाइंसा गांव में गंदे पानी से हुई मौतों और बीमारियों के फैलने ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस की महासचिव, पूर्व मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने इस घटना पर हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में खराब हो रहे पीने के पानी के सिस्टम की एक बुरी झलक है।

एसबी संवाददाता से बातचीत में सांसद सैलजा ने बताया कि सिर्फ 15 दिनों में 15 मौतें, जिनमें छह मासूम बच्चे भी शामिल हैं, प्रशासनिक लापरवाही की हद दिखाती है। उन्होंने कहा कि घरों में बिना सही क्लोरीनेशन या प्यूरिफिकेशन के पानी सप्लाई किया जा रहा था, जिससे जानलेवा बीमारियाँ हो रही हैं। टेस्ट किए गए 107 पानी के सैंपल में से 23 क्वालिटी चेक में फेल हो गए, और कई सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मिलना साफ दिखाता है कि लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया गया था। कुमारी सैलजा ने कहा कि 1,500 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, 800 से ज्यादा ओपीडी जांच और सैकड़ों ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के बाद भी सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। गाँव वाले बुखार, पीलिया, उल्टी और पेट दर्द से परेशान होते रहे, जबकि जिम्मेदार विभाग व अधिकारी चुपचाप देखते रहे।

कुमारी सैलजा ने कहा कि यह मामला सिर्फ पलवल तक ही सीमित नहीं है। सिरसा से लेकर पलवल तक, हरियाणा के कई हिस्सों में साफ पीने के पानी की भारी कमी और क्वालिटी की गंभीर चिंताएँ हैं। कुछ जगहों पर हेपेटाइटिस फैल रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कुमारी सैलजा ने सवाल किया कि जब लोगों के नलों तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, तो सरकार तथाकथित अमृत काल में तरक्की का दावा कैसे कर सकती है। अगर पानी ही जहर बन जाए तो आम नागरिक की जिंदगी कैसे सुरक्षित रह सकती है। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या गरीब और किसान समुदायों की जिंदगी को बेकार समझा जा रहा है। सैलजा ने छाइंसा घटना की हाई-लेवल और समय पर जांच, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, प्रभावित परिवारों को सही मुआवजा और पीने के पानी की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए राज्य भर में एक खास ड्राइव की मांग की ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो।

# दयालु-2 योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर समयबद्ध एवं नियमानुसार लिया जाए निर्णय: डीसी अपराजिता

## सरकार द्वारा तय मापदंडों हो शत प्रतिशत पालन

**एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार**

**कैथल।** डीसी अपराजिता ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक ली। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर समयबद्ध और नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाए ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल सके। इसमें सरकार द्वारा तय मापदंडों हो शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया।

डीसी अपराजिता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु-2 योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि) के हमले या काटने के कारण मृत्यु, स्थाई दिव्यांगता या गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी आपसी तालमेल से काम करें ताकि पात्र व्यक्तियों तक लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि) के काटने या हमले के कारण होने वाली मृत्यु, स्थायी विकलांगता में सरकार ने पीड़ित की आयु के आधार पर सहायता राशि को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। शून्य से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख रुपये तथा 45 से अधिक आयु के लिए 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार 70 से कम दिव्यांगता होने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 की सूची के अनुसार आनुपातिक लाभ दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर कुत्ता काटने की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के हिसाब से सहायता दी जाएगी।

इस अवसर पर आरटीए गिरीश कुमार, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीएसपी बीरभान, सीएमओ डा. रेणु चावला, जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्मल देवी, डीआईपीआरओ नसीब सैनी, जिला रेडक्रॉस सचिव रामजी लाल, प्लानिंग ऑफिसर विजेंद्र, नगर परिषद सचिव पवन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और संबंधित आवेदक भी उपस्थित रहे।

## सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'दो दीवाने सहर में' के साथ शुरू किया अपना रोमांटिक हीरो का सफर

सिद्धांत चतुर्वेदी अपने सिनेमाई सफर के एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां वह पहली बार पूरी तरह से रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते नजर आनेवाले हैं। फिलहाल फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के जरिए वह अपने अब तक के इंटेंस और लेयर्ड किरदारों से अलग, संवेदनशील, आकर्षक और भावनात्मक अंदाज में दिखाई देंगे। कई लोग इसे उनका 'लवर बॉय एरा' भी कह रहे हैं। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के साथ सिद्धांत एक ऐसे सिनेमा जगत में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उन्हें 'भंसाली हीरो' की पहचान मिल रही है। ये वो दुनिया है, जहां प्रेम काव्यात्मक होता है, भावनाएं गहरी होती हैं और कहानी कहने के कई अंदाज होते हैं। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि भंसाली से जुड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में एक विरासत और भव्यता का प्रतीक माना जाता है, और इस जोन में सिद्धांत का आना उनके करियर के विस्तार और विकास का संकेत देता है। गौरतलब है कि फिल्म में पहली बार उनकी जोड़ी मृणाल ठाकुर के साथ बनी है, जो फिल्म की ताजगी को और भी खास बनाती है। फिलहाल दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर शुरुआती झलकियों ने ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है और सिद्धांत को रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया है। ऐसे में यह कहें तो गलत नहीं होगा कि 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म 'दो दीवाने सहर में' से भंसाली हीरो के तौर पर सिद्धांत चतुर्वेदी की जगह पूरी तरह से पक्की हो गई है।

# क्या बॉन्ड गर्ल बनेंगी प्रियंका चोपड़ा?

## फिल्म में कास्टिंग को लेकर दिया हिंट

प्रियंका चोपड़ा की जल्द ही एक हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वह जबरदस्त एक्शन कर रही हैं। फैंस उनके एक्शन के कायल हो गए हैं। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की है। इसी दौरान उन्होंने 'बॉन्ड' सीरीज की अगली फिल्म को लेकर जिक्र किया। क्या वह सच में इसका हिस्सा हैं। जानिए, प्रियंका ने क्या कहा? और फैंस का इस बात पर क्या रिएक्शन रहा है?

### '007 बॉन्ड' सीरीज पर प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा?

वैरायटी को दिए गए हालिया इंटरव्यू में करियर को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने लंबी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने 007 बॉन्ड सीरीज की फिल्म को लेकर बड़ा हिंट दिया। वह कहती हैं, 'यह प्रोजेक्ट सच में ग्लोबल हो सकता है। मैं इस बात के लिए उत्साहित हूं कि मेकर्स कौन सा रास्ता चुनते हैं।' यह खबर सुनकर प्रियंका चोपड़ा के फैंस काफी खुश हैं। फैंस सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट बॉन्ड गर्ल बताने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।

### प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं?

प्रियंका चोपड़ा के करियर फ्रंट की बात करें तो वह हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' और राजामौली की पैन इंडिया फिल्म 'वाराणसी' का हिस्सा हैं। 'वाराणसी' फिल्म में प्रियंका चोपड़ा साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म बड़े स्तर पर बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्रियंका चोपड़ा लगातार भारत आ रही हैं। अब उनका नाम फिल्म '007 बॉन्ड' सीरीज को लेकर भी सामने आ रहा है। देखना होगा कि क्या सच में वह बॉन्ड गर्ल बनती हैं या नहीं।

## विशाल जेठवा ने जताई 'मर्दानी 4' में विलेन बनने की इच्छा

**विशाल जेठवा ने 'होमबाउंड' और 'मर्दानी 2' में शानदार अभिनय किया था। उनकी फिल्म 'होमबाउंड' तो ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में भी शॉर्टलिस्ट की गई थी। इस फिल्म में भी विशाल की एक्टिंग को फैंस ने काफी सराहा था। वहीं उन्होंने 'मर्दानी 2' में विलेन का रोल निभाया था। अब एक बार फिर विशाल विलेन का रोल निभाना चाहते हैं।**

### विशाल ने की रानी मुखर्जी की तारीफ

हाल ही में विशाल जेठवा 'मर्दानी 3' की स्पेशल स्क्रीनिंग में रानी मुखर्जी से दोबारा मिले। 'मर्दानी 3' में रानी की एक्टिंग की तारीफ करते हुए विशाल ने कहा, 'मर्दानी 2' फिल्म मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहेगी और रानी मैम भी। उनके साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीखने वाला अनुभव रहा है। वह ईमानदारी, मजबूती और बेहद सादगी के साथ लीड करती हैं। स्क्रीनिंग के दौरान उनसे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। मुझे 'मर्दानी 2' का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व महसूस होता है।' 'मर्दानी' फ्रेंचाइज और रानी की तारीफ करते हुए विशाल ने आगे कहा कि 'मर्दानी' और रानी मुखर्जी एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार को रानी मैम से बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता था। मैंने 'मर्दानी 3' देखी और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वे रानी मुखर्जी क्यों हैं। मैं चाहता हूं कि 'मर्दानी 4' में मैं विलेन बनकर वापसी करूं।'

# डाकू में साथ दिखेंगे अदिवि शेष और पवन सिंह

पैन-इंडिया एक्शन फिल्म डाकू में अदिवि शेष और भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर पवन सिंह डांस करते नजर आएंगे। यह गाना तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की एक साथ झलक दिखाएगा। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, भाई भोजपुरी और तेलुगु जिंदाबाद। बता दें, मृणाल ठाकुर अपनी शूटिंग खत्म कर चुकी हैं और अदिवि शेष ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी है। इसके बाद डाकू इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल हो गई है। अदिवि शेष के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जबकि अनुराग कश्यप एक अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन शनील देवो कर रहे हैं। डाकू को सुप्रिया यारलगड्डा ने प्रोड्यूस किया है। जबकि सुनील नारंग इसके को-प्रोड्यूसर हैं और फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियोज प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म की शूटिंग एक साथ हिंदी और तेलुगु में की गई है, जबकि इसकी कहानी और पटकथा अदिवि शेष और शनील देवो ने मिलकर लिखा है।

# मैं किसी की भी एक्ट्रेस जैसी नहीं पहली तान्या मित्तल बनना चाहूंगी

**तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर और बिग बॉस 19 में अपने बड़बोलेपन को लेकर चर्चा में रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर बातें साझा कीं। साथ ही किसी भी एक्ट्रेस को फॉलो ना करने की बात भी कही। तान्या मित्तल की इस बात पर यूजर्स ने भी रिएक्शन दिए हैं।**

तान्या मित्तल ने एक इंटरव्यू दिया। जिसमें वह कहती हैं, 'जब मैं बिग बॉस 19 से बाहर आई तो लोग सवाल करते थे कि आलिया भट्ट, करीना कपूर में से किसके जैसा बनना चाहोगी। तो मेरा जवाब होता था कि मैं किसी की जैसी नहीं बनना चाहूंगी। मैं पहली तान्या मित्तल बनना चाहूंगी।' तान्या के इस बयान पर कई यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा, 'तान्या क्वीन है।' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'आप सबसे अच्छी है। हेटर्स को पता नहीं है कि उन सब की हेट से तान्या का फैनबेस और स्ट्रॉन्ग हो रहा है।' इसी तरह एक फैन ने कमेंट किया, 'आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है जैसा आपने कहा तान्या मित्तल बनो, हम आपको वैसे ही प्यार करते हैं, जैसी आप हैं।'

### तान्या को मिला एकता कपूर से ऑफर

तान्या के करियर फ्रंट की बात करें तो बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। ब्रांन्ड प्रमोशन कर रही हैं। वहीं रियलिटी शो बिग बॉस 19 में प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी तान्या को एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था। जल्द ही वह उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं।

### शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापस आई रानी

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित 'मर्दानी 3' मर्दानी फ्रैंचाइज की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में जानकी बोडीवाला और मल्लिका प्रसाद भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आई हैं। मल्लिका प्रसाद फिल्म में अम्मा के किरदार में नजर आई हैं। फिल्म लड़कियों की तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है।

# संघर्ष और सफलता दोनों का अपना मजा

**'लैला मजनू' जैसी जुनूनी प्रेम कहानी वाली फिल्म से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली तृप्ति डिमरी इन दिनों एक और इंटेंस लव स्टोरी 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में हैं। तृप्ति इससे पहले गहरे इश्क वाली फिल्म 'धड़क 2' भी कर चुकी हैं, पर असल जिंदगी में वह जुनूनी नहीं, सच्चे प्यार में यकीन करती हैं। तृप्ति का कहना है, 'प्यार को लेकर हर किसी का अलग नजरिया होता है। हर कोई उसे अपने हिसाब से देखता है, लेकिन मैं बस सच्चे प्यार में यकीन करती हूं। जुनूनी- वुनूनी प्यार मुझे समझ में नहीं आता, पर सच्चे प्यार पर मुझे पूरा भरोसा है।'**

अपने करियर के शुरुआती दौर में तृप्ति ने तीन साल में तीन फिल्में की थीं, जबकि 'एनिमल' की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की झड़ी लगी हुई है। अकेले साल 2024 में वह 'बैड न्यूज', 'विकी विद्या का वो वाला विडियो' और 'भूल भुलैया 3' में नजर आईं। जबकि आने वाले दिनों में भी वह 'ओ रोमियो' के अलावा, 'स्पिरिट' और 'मां बहन' जैसी बड़ी फिल्मों में दिखेंगी। रिजेक्शन और इंतजार के लंबे दौर के बाद अब हर चौथी-पांचवीं फिल्म का ऑफर मिलने वाली इस सफलता के बारे में तृप्ति कहती हैं, 'मेरे लिए तो यह बहुत खुशी की बात है कि हर चौथी या पांचवीं फिल्म मेरे पास आ रही है। मैं तो चाहती हूं कि हर दूसरी फिल्म मेरे पास आए, क्योंकि मैंने काफी लंबा गैप भी देखा है।'

### पैरेंट्स को लगता था, पढ़ाई से बचने के लिए एक्टर बनना चाहती हैं तृप्ति डिमरी

तृप्ति डिमरी ने जब एक्टिंग में करियर बनाने का तय किया था, तब उनके पैरेंट्स काफी डरे हुए थे। वह उनके फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन अब उनकी कामयाबी देखकर वे फूले नहीं समाते। उनकी सोच में आए बदलाव पर तृप्ति कहती हैं, 'निश्चित तौर पर अब वे बहुत खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं। हालांकि, शुरुआत में भी उनकी जो सोच थी, जो डर था, उसके लिए मैं उन्हें गलत नहीं मानती, क्योंकि उनके लिए मुंबई एक बिल्कुल नया शहर था। वे किसी को जानते नहीं थे। ऐसे में, अपने बच्चे को यहां भेजना हर माता-पिता के लिए मुश्किल फैसला होता है। फिर, उनको यह भी नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग से इतना प्यार है। उन्हें लगता था कि इसको पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए एक्टिंग में जाना चाहती है (हंसती हैं)। लेकिन अब उन्हें बहुत गर्व होता है। कई बार वे मेरे इंटरव्यू चला देते हैं, जिस पर मैं झेंप जाती हूं, मगर वे बहुत ही ज्यादा खुश हैं और मैं खुश हूं कि वे खुश हैं।'

### गहरे समंदर में छोड़ देते हैं विशाल सर

फिल्म 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी का किरदार काफी इंटेंस और लेयर वाला है। इसकी तैयारी के बारे में वह बताती है, 'इस किरदार को समझने में मुझे विशाल सर (डायरेक्टर विशाल भारद्वाज) से बहुत मदद मिली। हर फिल्म, हर किरदार के साथ हमारी एक जर्नी होती है, जहां उनको समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। कम से कम मेरा प्रॉसेस ऐसा है कि मैं जानना चाहती हूं कि वो किरदार कैसे सोचता है? अलग-अलग लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसा है? उसके लिए मैंने अतुल मोंगिया सर के साथ काफी वर्कशॉप की। मेरे किरदार अफशां की चुनौतियां, परिस्थितियां आदि समझने की कोशिश की। उससे काफी कुछ सीखने को मिला। अगर मैं वो नहीं करती तो पहले दिन बहुत नर्वस होती। उसके अलावा, विशाल सर के साथ काम करना अपने में एक्टिंग वर्कशॉप है। वह कई बार आपको गहरे समंदर में छोड़ देते हैं। आपको लगेगा कि आपको सीन का सुर पता है पर फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, यह तो कुछ अलग है।'

### संघर्ष के कारण सफलता की कीमत समझती हैं तृप्ति

तृप्ति आगे कहती हैं, 'मैं काफी पहले से एक्टर बनने की कोशिश कर रही थी, मगर जब मुझे मौका मिला तो अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि, मैंने तब भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं असफल हूं। मैं तब भी बहुत खुश थी, जब ऑडिशन के लिए जाती थी। उसका अलग मजा था। आज जो चल रहा है, उसका अलग मजा है। सच कहूं तो अगर मैंने वो दिन नहीं देखे होते तो शायद मैं अपने करियर को उतना वैल्यू नहीं करती, जितना आज करती हूं।'